सारण जिले में खाद्य सुरक्षा और महिलाओं के जीवन पर इसका प्रभाव

अर्चना कुमारी*

*पी-एच॰डी॰ शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, बिहार

ईमेल: ashish0349@gmail.com

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.23291427

सारांश:

खाद्य सुरक्षा एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है और इसे मानव स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण तथा समाज की आर्थिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है। बिहार राज्य को अक्सर गरीबी, कुपोषण और मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। यहाँ महिलाएँ घरेलू खाद्य प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, फिर भी वे खाद्य असुरक्षा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील बनी रहती हैं। यह अध्ययन सारण जिले में खाद्य सुरक्षा के महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है, जिसमें खाद्य तक पहुँच, पोषण की स्थिति, कार्यभार, निर्णय-निर्माण और सामना करने की रणनीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस अध्ययन में गुणात्मक वर्णनात्मक पद्धति अपनाई गई है। प्राथमिक आँकड़े विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और जातीय पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं के साथ अनौपचारिक चर्चाओं, अर्ध-संरचित साक्षात्कारों और क्षेत्रीय अवलोकन के माध्यम से एकत्र किए गए हैं। इसके साथ ही, निष्कर्षों को संदर्भ प्रदान करने के लिए सरकारी रिपोर्टों, जनगणना अभिलेखों और शैक्षणिक अध्ययनों से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों का भी उपयोग किया गया है। अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन योजना जैसी सरकारी योजनाओं ने परिवारों की खाद्य तक पहुँच में सुधार किया है। फिर भी अनियमित आपूर्ति, भोजन की खराब गुणवत्ता, गरीबी, सामाजिक मानदंड और सीमित पोषण संबंधी जागरूकता जैसी संरचनात्मक चुनौतियाँ महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती रहती हैं। महिलाएँ मुख्य रूप से घरेलू खाद्य प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाती हैं और अक्सर बच्चों तथा पुरुष सदस्यों के भोजन को प्राथमिकता देने के लिए अपने पोषण से समझौता करती हैं।

यह अध्ययन रेखांकित करता है कि खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लैंगिक भूमिकाओं, सामाजिक असमानता और महिलाओं की एजेंसी से गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम जो महिलाओं को निर्णय-निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करें, पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाएँ और खाद्य सहायता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करें, वे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार, महिलाओं के सशक्तिकरण और

सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ावा दे सकते हैं। यह अध्ययन बिहार में खाद्य सुरक्षा से जुड़े महिलाओं के जीवन अनुभवों पर केंद्रित सूक्ष्म-स्तरीय शोध की कमी को भरने में योगदान देता है।

मुख्य शब्द: खाद्य सुरक्षा, महिलाएँ, लिंग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सारण जिला, बिहार, पोषण, घरेलू प्रबंधन।

परिचय:

खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि समाज के सभी व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक नियमित पहुँच प्राप्त हो। खाद्य और कृषि संगठन (FAO, 2020) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा के चार प्रमुख आयाम हैं: उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता। भारत में पहले की तुलना में आज कहीं अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है, फिर भी यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके, अब भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक बिहार को ऐसे विशिष्ट मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जो खाद्य असुरक्षा को और अधिक बढ़ा देते हैं।

बिहार की लगभग 88 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अधिकांश लोग छोटे पैमाने की कृषि, असंगठित श्रम और मौसमी रोजगार पर निर्भर हैं। (बिहार सरकार, 2022) आय की अस्थिरता, कम मजदूरी और लगातार होने वाला प्रवासन भोजन तक अनियमित पहुँच का कारण बनते हैं। महिलाएँ, जो घरेलू भोजन की तैयारी, राशन प्रबंधन और देखभाल कार्यों की मुख्य जिम्मेदारी निभाती हैं, खाद्य असुरक्षा से असमान रूप से अधिक प्रभावित होती हैं। भोजन की कमी के समय वे अक्सर सबसे अंत में भोजन करती हैं या कम पौष्टिक आहार ग्रहण करती हैं, जो खाद्य पहुँच में व्याप्त लैंगिक असमानताओं को दर्शाता है।

सारण जिला, जो उत्तरी बिहार में स्थित है, मुख्यतः कृषि आधारित है और इसमें ग्रामीण गाँवों के साथ-साथ छोटे शहरी केंद्र भी शामिल हैं। इस जिले में मौसमी प्रवासन, सीमित औद्योगिक विकास और दैनिक मजदूरी पर निर्भरता आम है, जो परिवारों को खाद्य असुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। यहाँ महिलाएँ घरेलू खाद्य प्रबंधन संभालती हैं, लेकिन निर्णय-निर्माण में उनकी भूमिका सीमित रहती है। सामाजिक मानदंड, जातिगत संरचनाएँ और गरीबी जैसे कारक सरकारी योजनाओं और अन्य सामाजिक संसाधनों तक उनकी पहुँच को प्रभावित करते हैं।

खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जो परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराती हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) माताओं और

बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करती है, जबकि मध्याह्न भोजन योजना विद्यालयों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराती है। इन योजनाओं ने खाद्य तक पहुँच में कुछ सुधार अवश्य किया है, लेकिन अनियमित आपूर्ति, निम्न गुणवत्ता का अनाज, प्रशासनिक अक्षमताएँ और सीमित जागरूकता जैसी समस्याएँ इनके पूर्ण प्रभाव में बाधा डालती हैं।

सारण जिले में खाद्य सुरक्षा के सामाजिक आयाम महिलाओं के अनुभवों से स्पष्ट होते हैं। वे सीमित संसाधनों का प्रबंधन करती हैं, परिवार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती हैं और मौसमी बेरोजगारी या सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करती हैं। कई महिलाओं ने बताया कि वे बच्चों और पुरुष सदस्यों को भोजन सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सबसे अंत में भोजन करती हैं, भोजन छोड़ देती हैं या भोजन की मात्रा कम कर देती हैं। कुछ महिलाओं ने कमी के समय पड़ोसियों से भोजन उधार लेने या स्थानीय सामुदायिक सहयोग पर निर्भर रहने की बात भी साझा की।

प्रवासन घरेलू खाद्य सुरक्षा को और जटिल बना देता है। परिवार अक्सर प्रवासी सदस्यों से प्राप्त धनराशि पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अनियमित प्रवासन के कारण अनिश्चितता के दौर आते रहते हैं। ऐसे समय में महिलाओं को सीमित संसाधनों के साथ घरेलू भोजन प्रबंधन करना पड़ता है, जिससे उनका शारीरिक और भावनात्मक कार्यभार बढ़ जाता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य सारण जिले की महिलाओं के दृष्टिकोण से खाद्य सुरक्षा को समझना है। यह उनके जीवन अनुभवों के माध्यम से भोजन तक पहुँच, पोषण, कार्यभार और एजेंसी के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। साथ ही यह घरेलू खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने में सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करता है। यह अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल आँकड़ों तक सीमित न रहकर खाद्य असुरक्षा के सामाजिक और मानवीय पहलुओं को उजागर करता है, जो नीति निर्माण और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

साहित्य समीक्षा:

खाद्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन किए गए हैं, जिनका मुख्य ध्यान अक्सर खाद्य उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और नीतिगत हस्तक्षेपों पर रहा है। प्रारंभिक शोध भोजन की उपलब्धता और वितरण पर केंद्रित थे, जबकि बाद के अध्ययनों ने खाद्य तक पहुँच, उपयोग और गरीबी, लिंग तथा शासन जैसे सामाजिक निर्धारकों को प्रमुखता दी है (FAO, 2020; World Bank, 2021)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना था, जो भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है। इस कानून से कवरेज में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विभिन्न अध्ययनों में बहिष्करण त्रुटियाँ, अनियमित आपूर्ति, खराब गुणवत्ता वाले अनाज और प्रशासनिक बाधाओं की ओर संकेत किया गया है, विशेष रूप से बिहार में (Joshi & Kumar, 2016; Khera, 2017)

लैंगिक दृष्टिकोण से किए गए शोध बताते हैं कि खाद्य असुरक्षा के संदर्भ में महिलाओं को विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर बच्चों और पुरुष सदस्यों के लिए अपने पोषण का त्याग करती हैं, जिससे कुपोषण, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं (Agarwal, 2017; Ghosh, 2019)। भोजन तैयार करने और घरेलू प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका उन्हें एक ओर जिम्मेदार बनाती है, तो दूसरी ओर उन्हें अधिक संवेदनशील भी बनाती है।

बच्चों या गर्भवती महिलाओं के लिए बनाई गई पोषण संबंधी योजनाएँ अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को लाभ पहुँचाती हैं, लेकिन प्रायः महिलाओं के अपने स्वास्थ्य और उनकी एजेंसी के मुद्दों को सीधे संबोधित नहीं करतीं।

बिहार में जिला-स्तरीय अध्ययनों से पता चलता है कि खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं। मौसमी रोजगार, प्रवासन, जाति और स्थानीय शासन घरेलू स्तर पर खाद्य उपलब्धता और पहुँच को प्रभावित करते हैं। महिलाएँ अक्सर भोजन का सीमित वितरण, उधार में भोजन लेना, सामुदायिक समूहों में भागीदारी करना या बच्चों के पोषण को प्राथमिकता देना जैसी रणनीतियाँ अपनाती हैं (Mishra & Yadav, 2019)। हालांकि, ये उपाय गरीबी, लैंगिक असमानता और प्रशासनिक अक्षमताओं जैसी संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते।

सैद्धांतिक दृष्टिकोण, जैसे अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण, इस बात पर जोर देता है कि खाद्य सुरक्षा केवल कैलोरी की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ और गरिमापूर्ण जीवन जीने की क्षमता से जुड़ी हुई है। यह दृष्टिकोण खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में महिलाओं की एजेंसी के महत्व को रेखांकित करता है। इसके बावजूद, बिहार के विशिष्ट जिलों में महिलाओं के अनुभवों पर केंद्रित सूक्ष्म-स्तरीय गुणात्मक शोध अभी भी सीमित हैं। अधिकांश अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों या व्यापक सर्वेक्षणों पर आधारित हैं, जिससे दैनिक जीवन, निर्णय-निर्माण और सामाजिक गरिमा पर खाद्य असुरक्षा के प्रभावों की अनदेखी होती है।

यह अध्ययन सारण जिले पर ध्यान केंद्रित कर और गुणात्मक अंतर्दृष्टियों को संदर्भात्मक विश्लेषण के साथ जोड़कर इन शोध अंतरालों को संबोधित करता है। यह महिलाओं को घरेलू खाद्य चुनौतियों से जूझने वाली सक्रिय एजेंट के रूप में प्रस्तुत करता है और इस प्रकार लैंगिक खाद्य सुरक्षा पर अकादमिक तथा नीतिगत विमर्श में योगदान देता है।

अनुसंधान के उद्देश्य:

1. बिहार के सारण जिले में घरेलू खाद्य सुरक्षा की स्थिति का आकलन करना।
2. खाद्य असुरक्षा का महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
3. घरेलू खाद्य प्रबंधन और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करना।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन योजना सहित सरकारी खाद्य योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
5. खाद्य असुरक्षा के लैंगिक आयामों को उजागर करना तथा महिलाओं की एजेंसी और कल्याण में सुधार के लिए रणनीतियों की पहचान करना।

अध्ययन का क्षेत्र:

1. अध्ययन सारण जिले पर केंद्रित है और इसमें ग्रामीण गांव और छोटे कस्बे शामिल हैं।
2. इसमें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं का विश्लेषण किया गया है, जिसमें हाशिए पर रहने वाले समूह भी शामिल हैं।
3. यह घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा की स्थिति का अध्ययन करता है, जिसमें उपलब्धता, पहुँच और उपयोग शामिल हैं।
4. सरकारी योजनाओं (पीडीएस, आईसीडीएस, मध्याह्न भोजन) और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है।
5. अध्ययन में गुणात्मक शोध पद्धतियों का उपयोग किया गया है, जैसे अनौपचारिक बातचीत, अर्ध-संरचित साक्षात्कार और क्षेत्रीय अवलोकन।
6. निष्कर्ष सारण जिले जैसे अन्य जिलों के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करते हैं और खाद्य सुरक्षा एवं महिलाओं के सशक्तिकरण को सुधारने के लिए नीति निर्माण में सहायक हैं।

अनुसंधान पद्धति:

यह अध्ययन महिलाओं के खाद्य सुरक्षा से जुड़े अनुभवों को समझने के लिए गुणात्मक और वर्णनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। गुणात्मक पद्धति सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंगिक आयामों की गहन पड़ताल की अनुमति देती है।

अध्ययन क्षेत्र:

सारण जिले का चयन इसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ग्रामीण और अर्ध-शहरी बस्तियों के मिश्रण, मौसमी प्रवासन के स्वरूप और असंगठित श्रम पर निर्भरता के कारण किया गया।

नमूना चयन:

उद्देश्यपूर्ण नमूना विधि के अंतर्गत विभिन्न गाँवों, जाति समूहों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से महिलाओं का चयन किया गया। इससे विविधता सुनिश्चित हुई और घरेलू खाद्य प्रबंधन से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण सामने आए।

डेटा संग्रह:

1. ***प्राथमिक डेटा*:**
   महिलाओं के साथ अनौपचारिक चर्चाएँ और अर्ध-संरचित साक्षात्कार किए गए, जिनका केंद्र खाद्य तक पहुँच, पोषण, राशन के उपयोग, कार्यभार और सामना करने की रणनीतियाँ रहीं। घरों और राशन दुकानों में क्षेत्रीय अवलोकन भी किया गया।
2. ***द्वितीयक डेटा:***
   निष्कर्षों को संदर्भ प्रदान करने के लिए सरकारी रिपोर्टों, जनगणना अभिलेखों, नीतिगत दस्तावेजों और शैक्षणिक अध्ययनों का उपयोग किया गया।

डेटा विश्लेषण:

1. विषयवस्तु विश्लेषण के माध्यम से खाद्य तक पहुँच, सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता, स्वास्थ्य और पोषण पर प्रभाव, घरेलू स्तर पर वितरण और महिलाओं की एजेंसी से जुड़े पैटर्न की पहचान की गई।
2. कथात्मक विवरणों का विश्लेषण बार-बार सामने आने वाली चुनौतियों, सामना करने के उपायों और नीतिगत निहितार्थों के संदर्भ में किया गया।

नैतिक विचार:

1. अध्ययन में भागीदारी स्वैच्छिक थी और प्रतिभागियों को अध्ययन के उद्देश्यों की जानकारी दी गई।
2. गोपनीयता और पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
3. सांस्कृतिक संवेदनशीलता और प्रतिभागियों की गरिमा का पूर्ण सम्मान बनाए रखा गया।

निष्कर्ष और चर्चा

1. ***खाद्य तक पहुँच और सरकारी योजनाएँ***

   अधिकांश परिवार बुनियादी खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर निर्भर हैं। महिलाओं ने खाद्य तक पहुँच में सुधार की बात कही, लेकिन अनियमित आपूर्ति और कभी-कभी खराब गुणवत्ता वाले अनाज की शिकायत भी की। आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन योजनाएँ बच्चों के पोषण को समर्थन देती हैं और महिलाओं के कार्यभार को कुछ हद तक कम करती हैं।

2. ***घरेलू खाद्य प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका***

   महिलाएँ भोजन से जुड़े सभी कार्यों का प्रबंधन करती हैं, जिनमें खाना पकाना, भोजन का सीमित वितरण और बच्चों व पुरुष सदस्यों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करना शामिल है। कमी की स्थिति में वे अक्सर सबसे अंत में भोजन करती हैं या भोजन छोड़ देती हैं। एक उत्तरदाता ने कहा, "मैं आमतौर पर तभी खाती हूँ जब मेरे बच्चे पेट भरकर खा लें। कई बार मैं दोपहर का भोजन छोड़ देती हूँ ताकि वे ठीक से खा सकें।"

3. ***स्वास्थ्य और पोषण पर प्रभाव***

   सीमित और खराब गुणवत्ता वाला भोजन थकान, एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। पोषण के प्रति कम जागरूकता और पारंपरिक खानपान की आदतें इन समस्याओं को और बढ़ा देती हैं। कुपोषण महिलाओं की घरेलू कार्य करने और बच्चों की देखभाल करने की क्षमता को कम कर देता है।

4. ***सामाजिक-आर्थिक कारक***

   गरीबी, मौसमी रोजगार और प्रवासन खाद्य असुरक्षा को बढ़ाते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएँ इससे सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। पुरुष सदस्यों का प्रवासन अक्सर महिलाओं के कार्यभार और मानसिक तनाव को बढ़ा देता है।

5. ***सामना करने की रणनीतियाँ और एजेंसी***

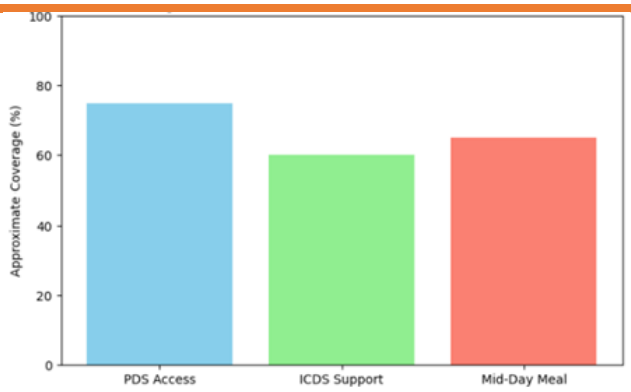
महिलाएँ भोजन का सीमित वितरण, उधार में भोजन लेना, स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी करना और बच्चों को प्राथमिकता देना जैसी रणनीतियाँ अपनाती हैं। ये उपाय अल्पकालिक संकटों में प्रभावी होते हैं, लेकिन संरचनात्मक असमानताओं का समाधान नहीं कर पाते।

तालिका संख्या–1 : सारण जिला में खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष एवं महिलाओं की सामना करने की रणनीतियाँ

अध्ययन के क्षेत्र	प्रमुख निष्कर्ष	महिलाओं द्वारा अपनाई गई सामना करने की रणनीतियाँ
खाद्य उपलब्धता एवं पहुँच	अधिकांश परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर निर्भर हैं, किंतु राशन की आपूर्ति अनियमित रहती है तथा गुणवत्ता संतोषजनक नहीं होती	पड़ोस या रिश्तेदारों से भोजन उधार लेना; भोजन की मात्रा में कटौती करना
सरकारी पोषण योजनाएँ	एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) एवं मध्याह्न भोजन योजना से बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है, परंतु महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ सीमित है	स्वयं सहायता समूहों में सहभागिता; सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया को समझने का प्रयास
स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति	महिलाओं में थकान, कमजोरी, अल्पपोषण तथा सामान्य बीमारियाँ प्रचलित हैं	बच्चों को प्राथमिकता देना; घरेलू एवं स्थानीय उपचारों का सहारा लेना
घरेलू उत्तरदायित्व	भोजन से संबंधित सभी कार्यों की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है; भोजन की कमी के समय महिलाएँ सबसे अंत में भोजन करती हैं	भोजन का संतुलित वितरण; भोजन की योजना में समायोजन
सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ	गरीबी, मौसमी रोजगार तथा पुरुषों का पलायन खाद्य असुरक्षा को बढ़ाता है	घरेलू कार्यों का आपसी बँटवारा; अनौपचारिक सामाजिक सहयोग नेटवर्क का उपयोग
निर्णय-निर्माण एवं सहभागिता	राशन प्राप्ति अथवा शिकायत दर्ज कराने में महिलाओं की भूमिका सीमित है	सामुदायिक समूहों से जुड़ाव; अनौपचारिक स्तर पर अपनी समस्याएँ रखना

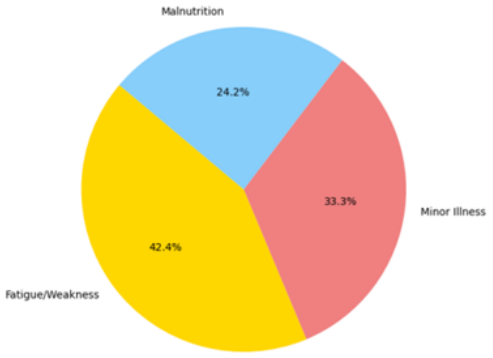
चित्र–1 : सारण जिला में सरकारी खाद्य योजनाओं का कवरेज

IJSSRA l ISSN (online): 3107-6238
July-September 2026 l Vol. 02 l Issue 2



यह स्तंभ आरेख (Bar Chart) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) तथा मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या के अनुमानित कवरेज को दर्शाता है।

चित्र–2 : खाद्य असुरक्षा का महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव



यह वृत्त आरेख (Pie Chart) खाद्य असुरक्षा के कारण महिलाओं में पाई जाने वाली स्वास्थ्य समस्याओं—जैसे थकान/कमजोरी, सामान्य बीमारियाँ तथा कुपोषण से प्रभावित महिलाओं के अनुपात को प्रदर्शित करता है।

विवेचना

यह अध्ययन सारण जिला में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को केवल भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संरचनाओं, लैंगिक भूमिकाओं और आर्थिक असमानताओं के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित ***क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach)*** के अनुसार, विकास का वास्तविक अर्थ केवल आय या संसाधनों की उपलब्धता नहीं है, बल्कि व्यक्तियों की यह क्षमता है कि वे अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। इस दृष्टि से देखा जाए तो सारण जिला की महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा का प्रश्न उनकी स्वास्थ्य क्षमता, निर्णय-निर्माण क्षमता और सामाजिक भागीदारी से सीधे जुड़ा हुआ है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से खाद्य उपलब्धता में वृद्धि हुई है, किंतु महिलाओं की वास्तविक क्षमताओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाज की उपलब्धता महिलाओं की भौतिक आवश्यकता को तो कुछ हद तक पूरा करती है, लेकिन भोजन के वितरण, उपभोग और गुणवत्ता पर महिलाओं का नियंत्रण सीमित रहता है। यह स्थिति सेन के दृष्टिकोण के अनुसार एक ***"संसाधन–क्षमता अंतर"*** को दर्शाती है, जहाँ संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद महिलाएँ उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पातीं।

जेंडर थ्योरी के अनुसार, घरेलू कार्यों और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों को पारंपरिक रूप से महिलाओं से जोड़ा जाता है, जबकि निर्णय-निर्माण और संसाधन नियंत्रण पुरुषों के अधीन रहता है। इस अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि भोजन प्रबंधन, पकाने और वितरण की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है, किंतु भोजन की मात्रा, गुणवत्ता और खर्च से जुड़े निर्णयों में उनकी भूमिका सीमित रहती है। यह स्थिति ***पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना*** को दर्शाती है, जहाँ महिलाओं का श्रम अदृश्य रहता है और उनका स्वास्थ्य द्वितीयक महत्व रखता है।

महिलाओं द्वारा स्वयं सबसे अंत में भोजन करना या भोजन की मात्रा कम करना केवल व्यक्तिगत त्याग नहीं है, बल्कि यह सामाजिक रूप से निर्मित लैंगिक अपेक्षाओं का परिणाम है। जेंडर थ्योरी इस व्यवहार को ***लैंगिक असमानता के आंतरिकीकरण*** के रूप में देखती है, जहाँ महिलाएँ परिवार के हित को अपने स्वास्थ्य से ऊपर रखती हैं। इसका दीर्घकालिक प्रभाव महिलाओं में एनीमिया, कमजोरी और कार्यक्षमता में कमी के रूप में दिखाई देता है, जो अंततः पूरे परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है।

इसके अतिरिक्त, मौसमी पलायन और गरीबी महिलाओं की स्थिति को और जटिल बना देते हैं। जब पुरुष रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, तो महिलाओं पर घरेलू प्रबंधन, बच्चों की देखभाल और खाद्य संकट से निपटने का अतिरिक्त भार आ जाता है। सेन के क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार, इस स्थिति में महिलाओं की स्वतंत्रता और विकल्प और भी सीमित हो जाते हैं, क्योंकि वे बढ़े हुए उत्तरदायित्वों के बावजूद संसाधनों और निर्णयों पर नियंत्रण नहीं रखतीं।

हालाँकि, अध्ययन यह भी दर्शाता है कि जो महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों या सामुदायिक संगठनों से जुड़ी होती हैं, उनकी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होती है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएँ जानकारी साझा करती हैं, सरकारी योजनाओं तक पहुँच बनाती हैं और सामूहिक रूप से समस्याओं को उठाती हैं। यह स्थिति जेंडर थ्योरी के उस पक्ष को रेखांकित करती है, जहाँ

सामूहिकता और सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाएँ पितृसत्तात्मक सीमाओं को चुनौती देती हैं। सेन के दृष्टिकोण से यह महिलाओं की क्षमताओं के विस्तार का उदाहरण है, जिसमें वे केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि सक्रिय सहभागी बनती हैं।

इस सैद्धांतिक विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि खाद्य सुरक्षा नीतियों को केवल वितरण आधारित नहीं, बल्कि ***क्षमता निर्माण आधारित*** होना चाहिए। महिलाओं को प्रत्यक्ष पोषण सहायता, पोषण संबंधी शिक्षा और घरेलू निर्णय-निर्माण में भागीदारी देने से ही वास्तविक खाद्य सुरक्षा संभव है। जब महिलाओं की स्वास्थ्य क्षमता, जानकारी और सामाजिक आवाज़ मजबूत होती है, तब खाद्य सुरक्षा पूरे परिवार और समुदाय के लिए स्थायी बनती है।

अंततः, सारण जिला के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को यदि सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के ढाँचे में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना खाद्य सुरक्षा अधूरी है। अतः नीतिगत हस्तक्षेपों में महिलाओं को केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि ***अधिकारधारी और निर्णयकर्ता*** के रूप में स्थापित करना आवश्यक है।

शोध अंतराल:

बिहार में महिलाओं के जीवनानुभवों पर आधारित सूक्ष्म स्तर के गुणात्मक शोध सीमित हैं। अधिकांश अध्ययन मात्रात्मक आँकड़ों या राष्ट्रीय स्तर के विश्लेषण तक ही सीमित रहे हैं, जिससे घरेलू स्तर की लैंगिक गतिशीलता और संसाधन वितरण की वास्तविकता अनदेखी रह गई है। महिलाओं की सामना करने की रणनीतियों और सशक्तिकरण पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। यह अध्ययन जिला-स्तर पर महिलाओं के अनुभवों को केंद्र में रखकर इन अंतरालों को भरने का प्रयास करता है और नीति निर्माण के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

सारण जिले में खाद्य सुरक्षा का महिलाओं के स्वास्थ्य, दैनिक कार्यभार और सामाजिक जिम्मेदारियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन जैसी सरकारी योजनाओं ने भोजन तक पहुँच में सुधार किया है, लेकिन अनियमित आपूर्ति, निम्न गुणवत्ता वाले अनाज, गरीबी और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ अब भी महिलाओं के लिए इन योजनाओं के प्रभाव को सीमित करती हैं। महिलाएँ घरेलू भोजन प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदार होती हैं, लेकिन अक्सर बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को प्राथमिकता देने के लिए खुद कम भोजन करती हैं। मौसमी पलायन, कम आय और सामाजिक असमानताएँ उनके कार्यभार और तनाव को

और बढ़ा देती हैं। भोजन की मात्रा घटाना, उधार लेना या सामुदायिक मदद पर निर्भर होना जैसी रणनीतियाँ केवल अस्थायी राहत देती हैं और मूल समस्याओं का समाधान नहीं करतीं।

खाद्य सुरक्षा सुधारने के लिए आवश्यक है कि महिलाएँ घर और समुदाय में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हों। सरकारी योजनाओं के माध्यम से लगातार और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। महिलाओं, विशेषकर माताओं, को प्रत्यक्ष पोषण सहायता और पोषण, अधिकार और सरकारी लाभ के बारे में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही गरीबी, सामाजिक असमानता और पलायन से जुड़ी चुनौतियों को भी दूर करने वाली नीतियाँ बनाई जानी चाहिए।

महिलाओं को सशक्त बनाना और भोजन तक समान पहुँच सुनिश्चित करना न केवल महिलाओं के लिए बल्कि बच्चों, परिवार और पूरे समुदाय के लिए लाभकारी है। सारण जिले में स्थायी खाद्य सुरक्षा केवल सामाजिक और संरचनात्मक चुनौतियों दोनों को एक साथ हल करने से ही संभव है।

संदर्भ:

1. Kumar, R. (2025). बिहार में आदिवासी समुदायों के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और सतत विकास लक्ष्य. *International Journal of Science and Social Science Research*. https://www.ijsssr.com/j/article/view/397
2. Hannan, A., & Raj, S. (2025). Household dependence on the public distribution system in Bihar. *Journal of Informatics Education and Research*. https://www.jier.org/index.php/journal/article/view/3462
3. शर्मा, आलख एन. (2023). ग्रामीण बिहार में गरीबी और खाद्य सुरक्षा. *Institute for Human Development रिपोर्ट*. https://www.ihdindia.org/research/security-and-vulnerability/poverty-and-food-security-in-rural-bihar/
4. Kumari, S., et al. (2023). Public distribution system of Bihar. *Journal of Business Management and Information Systems*. https://www.researchgate.net/publication/369372796_Public_Distribution_System_of_Bihar
5. Naik, P., et al. (2023). Household-level food insecurity and its correlates in rural Bihar. *Journal of Family Medicine and Primary Care*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10657071/
6. Institute for Human Development. (2018). *Food Security Atlas of Bihar*. https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/the-food-security-atlas-of-bihar-2018/

7. स्वाति, श. (2025). Implementation of food security act—impact on women's health and nutrition: A study of Bihar. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*. https://www.ijhssi.org/papers/vol14%286%29/1406139145.pdf
8. भारत सरकार. (2013). *National Food Security Act, 2013*. भारत सरकार।
9. Food and Agriculture Organization. (2020). *The state of food security and nutrition in the world 2020*. FAO.
10. World Bank. (2021). *Food security and nutrition global report*. World Bank.
11. भारत सरकार. (2011). *Census of India 2011: Social and Economic Status Report, Bihar*. Government of India.
12. बिहार सरकार. (2022). *Annual Report, Food and Consumer Protection Department, Bihar*.
13. भारत सरकार. (2024). *Mid-Day Meal Scheme Guidelines*. Ministry of Education.
14. भारत सरकार. (2024). *Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme Guidelines*. Ministry of Women and Child Development.
15. Joshi, A., & Kumar, S. (2016). Challenges in PDS implementation in Bihar. *Indian Journal of Public Administration*.
16. Khera, R. (2017). Food security and public distribution system in India. *Economic & Political Weekly*, 52(5), 34–42.
17. Agarwal, B. (2017). Gender and food security. *Journal of Rural Studies*, 50, 89–98.
18. Ghosh, A. (2019). Women's nutrition and food access in rural India. *Journal of Health Management*, 21(3), 345–360.
19. Mishra, P., & Yadav, R. (2019). Food security strategies among women in Bihar. *Asian Journal of Social Science Research*, 11(2), 56–72.
20. Food and Agriculture Organization. (2020). *Food security indicators and gender dimensions*. FAO.
21. Census of India. (2021). *NFHS-5 (National Family Health Survey-5) Data for Bihar*. Government of India.
22. भारत सरकार. (2024). *State Food Security Index 2024*. Ministry of Food and Consumer Affairs.
23. भारत सरकार. (2024). *Public Distribution System (PDS) Control Order*. Government of India.
24. राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग. (2024). *Health and Nutrition Report 2024*. Government of India.